गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव की फैक्ट्री पर आयकर विभाग की रेड

कोटपूतली के पाथरेड़ी स्थित राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड फैक्ट्री का मामला

- आई.टी. विभाग की टीम सुबह करीब 8 बजे फैक्ट्री पहुंची और दस्तावेज खंगालने में जुटी।
- इस कार्रवाई के बाद प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई।
- गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि, करीब 50 सालों से उनका परिवार कारोबार से जुड़ा है, उन्होंने कार्रवाई को राजनीति द्वेष से प्रेरित बताया।

जयपुर, 7 सितम्बर (का.प्र.)। बुधवार सुबह आयकर विभाग की कई टीमों ने देश के चार राज्यों में एक साथ छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दिया और यह कार्यवाही देर शाम तक जारी थी। आयकर विभाग की टीमों ने राजस्थान दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में एक साथ छापेमारी की कार्यवाही की है। इस कार्यवाही के तहत राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के कई ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ रेड की। बताया जाता है कि यह छापेमारी मिड-डे मील की सप्लाई में गड़बड़ी को लेकर हुई है।

राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव सहित उनके कई रिश्तेदारों के यहां आयकर विभाग की कार्यवाही एक साथ शुरू हुई। मंत्री के जयपुर स्थित, सिविल लाइन्स के सरकारी आवास, मालवीय नगर स्थित निजी आवास और उनके रिश्तेदारों के यहां सुबह से ही टीमें सर्च में जुट गईं। हालांकि आयकर विभाग की इस कार्यवाही को लेकर मंत्री राजेंद्र यादव का कहना है कि, हमारा मिड डे मील से कोई लेना देना नहीं है।

आयकर विभाग की यह कार्यवाही मंत्री और उनके रिश्तेदारों की कोटपूतली स्थित कंपनी, राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग फैक्ट्री सहित अन्य ठिकानों पर हुई है। गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो उनका बड़ा बेटा मधुर यादव प्रबंधक है।

बुधवार को सुबह 5.30 बजे मंत्री राजेंद्र यादव और उनके रिश्तेदारों के जयपुर और कोटपूतली स्थित 50 से ज्यादा ठिकानों पर विभाग के अधिकारी पहुंचे उनके साथ बड़ी संख्या में सी.आर.पी.एफ. के जवान थे। यादव कोटपूतली से दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने हैं। कोटपूतली में उनके रिश्तेदारों की एक फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में मिड-डे मील सप्लाई के लिए कट्टे बनाए जाते हैं। आयकर विभाग की ओर कार्रवाई में लगभग 100 वाहनों का भी इस्तेमाल किया गया है। आयकर विभाग की टीमों ने जयपुर में मंत्री के बेटों के घर सहित उनके उत्तराखंड, गुड़गांव स्थित व्यवसायिक और आवासीय ठिकानों पर छापा मारा।

जयपुर में राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास और बनीपार्क के निजी आवास सहित मालवीय नगर के ऑफिस में भी इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे। सूत्रों ने बताया है कि मिड-डे मिल और पौष्टिक आहार बनाने वाले निर्माता, सप्लाई करने वालों, उनके सहयोगियों और परिचितों के यहां रेड की जा रही है। कोटपूतली के पाथरेड़ी स्थित राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड फैक्ट्री पर भी आयकर विभाग के करीब 10 से 15 अधिकारियों व सीआरपीएफ के जवानों की टीम ने सुबह करीब 8 बजे पहुंच कर रेड की कार्यवाही शुरू की। जहां कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में बाहरी लोगों सहित मीडिया का प्रवेश भी बंद कर दिया गया। कार्रवाही के बाद प्रदेश में सियासी हलचल भी बढ़ गई है और अफवाहों का बाजार गर्म है।

गृह राज्यमंत्री यादव ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि वे राजनीति में आने से पूर्व से व्यापार कर रहे हैं। करीब 50 सालों से उनका परिवार कारोबार से जुड़ा हुआ है। आईटी की कार्यवाही को लेकर उन्होंने कहा कि आयकर विभाग का हम पूरा सहयोग करेंगे। यदि आईटी टीम को जांच के दौरान कोई गलत चीज लगती है तो हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा। यादव ने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर यह कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पाथरेड़ी स्थित उक्त फैक्ट्री में केवल प्लास्टिक के कट्टे बनाए जाते हैं जो विभिन्न पैकिंग से जुड़ी फर्मों को सप्लाई किए जाते हैं।

यादव ने कहा कि इनकम टैक्स जांच करे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमने साफ सुथरा काम किया है। इसी के साथ यादव ने कहा कि आयकर की कारवाई में कोई राजनीतिक दुर्भावना होगी, तो वह भी सामने आ जाएगी। आयकर विभाग की कार्यवाही को पॉलिटिकल फंडिंग से जोड़ने पर यादव ने कहा कि पॉलिटिकल फंडिंग से नाम जोड़ना गलत है। हमारा पैकेजिंग का काम है। मिड डे मील से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम कट्टे और पैकेजिंग समान बनाते हैं। यहां से कट्टे जाने के बाद उसमें कोई क्या भरता है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।

नीतीश एवं शरद पवार

नयी दिल्ली, 7 सितम्बर (वार्ता)। बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल (यू) के शीर्ष नेता नीतीश कुमार ने राजधानी के अपने प्रवास के दौरान विपक्षी नेताओं के संपर्क अभियान के क्रम में बुधवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार से मुलाकात की और अगले आम चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता की संभावनाओं पर चर्चा की। कुमार दिल्ली में पवार के निवास पर गये और वहां करीब 45 मिनट रहे। बैठक के बाद कुमार ने कहा कि विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ेगा तो देश के लिए अच्छा रहेगा।

बंधुआ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जोर देकर कहा कि देश में बंधुआ मजदूर के बहाने एक रैकिट चल रहा है। बैंच ने कई पहलुओं पर सरकार की विस्तृत प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि "सरकार जरूरी होने पर कानून के अंतर्गत उपचारात्मक कदम उठाएगी।"

जस्टिस गुप्ता ने बड़ी रूखाई से कहा कि कथित बंधुआ मजदूर वास्तव में बंधुआ नहीं हैं, वे काम के बदले धन लेते हैं लेकिन उसे बीच में छोड़ देते हैं।

उन्होंने टिप्पणी की "उन्हें ईंट भट्टे वाले काम पर रखते हैं। ये लोग पिछड़े क्षेत्रों के हैं। वे पैसा लेकर खा जाते हैं और काम बीच में छोड़ देते हैं। यह एक रैकिट है। ये मजदूर बंधुआ मजदूरों के नाम पर लाभ उठाते हैं।"

'मक्खन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और देश को संगठित रख सकते हैं।

कांग्रेस में यह मज़ाक चल रहा है कि कन्याकुमारी तथा आस-पास के इलाकों में अमूल बटर खत्म हो गया है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी पर भर-भर कर मक्खन लगा दिया है।

गहलोत का एजेण्डा साफ और सीधा है। अगर राहुल कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो गहलोत के लिये अच्छा रहेगा क्योंकि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और अगर गहलोत पार्टी अध्यक्ष बना दिये जाते हैं तो भी वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे। यह उनकी पहली एवं अंतिम प्राथमिकता है और इसे हासिल करने के लिये, राहुल गांधी को अमूल मक्खन लगाया जा रहा है।

यह ड्रामा सोनिया गांधी के वापस आ जाने के बाद शुरू होगा, तथा जब जो कुछ गहलोत चाहते हैं, उसे पाने के लिये वे संभवत: एडी-चोटी का जोर लगा देंगे तथा अपने मन्तव्य एवं एजेण्डा को आगे बढ़ाने के लिये गांधी परिवार के प्रति अपनी नज़दीकी का लाभ लेना चाहेंगे। जो भी है, वे यह सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त नहीं कर सकें।

लेकिन सूत्रों का कहना है कि राहुल ने इस बिन्दु पर बड़ा सख्त रूख इख्तियार कर लिया है कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा तथा माँ सोनिया को भी यह बात माननी ही होगी।

अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिये राहुल गांधी की पसंद हैं और वे ऐसा होते हुआ देखने के लिये वे जी-जान से लगे हुये हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि गांधी परिवार पार्टी नेतृत्व से अवकाश ले, तथा इस प्रक्रिया में वे अशोक गहलोत की राजस्थान से विदाई का उपयोग सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के लिये कर सकें, और गहलोत राहुल की इस योजना को पूरा न होने देने में बुरी तरह जुटे हुये हैं।

भाजपा के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में कमल के खिलने की कोई खास गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। इन विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा हिन्दुत्व से जुड़े मुद्दे जितना ज्यादा जोर-शोर से उठायेगी, उसके लिये मतदाताओं को बड़ी संख्या में प्रभावित करने की गुंजाइश उतनी ही कम होती जायेगी, क्योंकि तमिलनाडु के मतदाता जातिगत सोच एवं लिहाज तथा पार्टी के साथ मजबूत जुड़ावों से ज्यादा प्रभावित होते रहे हैं। यह बात सही हो या गलत, लेकिन भाजपा को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा जाता है जो ब्राह्मण एजेण्डा को आगे बढ़ाती है तथा यह चीज अन्य जातियों के लोगों को उससे दूर कर देती है।

अखिलेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाये जाने की अविश्वसनीय पेशकश कर दी है।

विपक्ष को एकजुट करने के अपने मिशन को जारी रखते हुये, बिहार के मुख्यमंत्री ने आज एन.सी.पी. प्रमुख शरद पवार तथा शरद यादव के साथ भी मीटिंग कीं। इसके अलावा, उन्होंने इस समय अस्वस्थ चल रहे सपा-संस्थापक मुलायम सिंह यादव से भी भेंट की। अखिलेश यादव ने मंगलवार को यह पेशकश कर दी कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायकों को साथ लेकर भाजपा से संबंध-विच्छेद कर लें तो वे मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिये मौर्य का समर्थन कर देंगे। यह प्रस्ताव रखते हुये, अखिलेश उत्तर प्रदेश भाजपा में अंदरूनी लड़ाई की स्थिति पैदा करने की रूपरेखा बना रहे हैं।

रूस/चीन व अमेरिका के तनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुखपत्र बन गया है जो कि यूक्रेन वॉर पर पुतिन का पक्ष ही प्रस्तुत करता है।

बीजिंग विंटर ओलम्पिक्स से पहले और पुतिन द्वारा यूक्रेन में रुस की सैन्य घुसपैठ की अनुमति से पूर्व शी एवं पुतिन बीजिंग में मिले थे तथा दोनों ने दोनों देशों के बीच "लिमिटलैस" (असीमित) दोस्ती की घोषणा की गई थी।

भारत इन दोनों मित्रों के बीच फंस गया है बिल्कुल "एलिस इन वंडरलैंड" की तरह भारत को भी रुस और पश्चिम के साथ संबंधों में संतुलन बनाना है, चीन के साथ बढ़ते टकराव के संदर्भ में।

जहां भारत के रुस के साथ अच्छे सम्बंध हैं लेकिन चीन भारत से लगती सीमा पर समस्याएं खड़ी करता रहता है।

- अब तक तो भारत चीन/रूस व अमेरिका के तनावों के बीच बहुत चतुराई से अपना काम चलाता रहा है, पर चीन/रूस और आक्रामक हुए, तो यह संतुलन बिठाना और कठिन हो जायेगा।

ऐसे ही एक सैन्य टकराव में भारत के 21 जवान शहीद हो गए थे।

दोनों निरंकुश तंत्र रुस और चीन एक साथ आ गए हैं और दोनों के हित एक जैसे हैं क्योंकि दोनों ही स्थापित कूटनीतिक प्रक्रिया को दरकिनार कर रहे हैं और सैन्य हस्तक्षेप से समस्याएं सुलझाना चाहते हैं। जहां रुस ने यूक्रेन में घुसपैठ की है वहीं चीन भी ताईवान को ताकत के बल पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है।

इसके अलावा चीन दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर भी दावा कर रहा है और इस क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय शिपिंग चैनल के रुप में प्रयुक्त करने से रोक रहा है, जहां से वैश्विक व्यापार होता है।

इससे भी बुरी बात है कि चीन सीमा पर भी तनाव पैदा कर रहा है और सीमा पर स्थित कई क्षेत्रों को अपना बता रहा है। चीन हिंद महासागर में अपने बेस बनाकर भारत को घेर रहा है। इसने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नौसैनिक बेस बनाया है। जहां से यह हिंद महासागर में शक्ति प्रदर्शन कर सकता है। इसके अलावा चीन ने श्रीलंका में भी एक प्रमुख बंदरगाह "हम्बनटोटा" पर कब्जा कर लिया है, जहां हाल ही में इसने कथित तौर पर एक रिसर्च नौका भेजी थी जो भारतीय सैटेलाइट को ट्रैक कर सकती है।चीन के साथ इस टकराव पूर्ण रिश्ते में भारत ने अमेरिका से काफी सहयोग व समर्थन लिया है इसने भारत तो उसके पारम्परिक मित्र रूस से दूर कर दिया है। रूस और अमेरिका के बढ़ते टकराव के बाद भी भारत ने दोनों देशों के बीच चतुराई से संतुलन बनाया है। भारत ने पश्चिम के प्रतिबंधों को ठुकरा कर रूस से तेल खरीदना जारी रखा साथ ही चीन के साथ लगती सीमा पर तैनात करने के लिए अमेरिका से हथियार खरीदे।

आयकर विभाग ने गैर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनावी पैनल ने यह भी घोषणा की थी कि वह 21 सौ से अधिक ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिन्हें धन के अंशदानों की प्रतिष्ठियां करने सहित चुनाव के नियम-कायदों का उल्लंघन करने के कारण पंजीकृत किन्तु गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन संस्थाओं ने अपने कार्यालयों के पते और पदाधिकारियों के नाम तक अपडेट नहीं किए हैं। उसने कहा था कि इनमें से कुछ पार्टियां "गंभीर" वित्तीय अनियमितताओं में संलग्न हैं।

चुनावी पैनल के अनुसार उसने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की। इन अधिकारियों ने रिपोर्ट दी थी कि सत्यापन के दौरान इन पार्टियों को या तो अस्तित्वहीन पाया गया था जब उनके पते और संवाद के विवरणों के सत्यापन के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा उन्हें पत्र भेजे गए तो वे पुन: लौट आए। डाक विभाग ने भी इन पत्रों को अनडिलीवर्ड माना है। चुनाव आयोग ने इसके बाद इन पार्टियों को सिम्बल्स ऑर्डर (1968) के अन्तर्गत मिले कई लाभों को वापस लेने का निर्णय लिया। इन लाभों में कॉमन इलैकशन सिम्बल का आवंटन भी शामिल है। गत जून माह में जारी एक बयान में चुनावी पैनल ने कहा था कि निर्णय से व्यथित कोईभी रजिस्टर्ड अनरिकग्नाईज़ड पॉलीटिकल पार्टी (आर.यू.पी.पी.) 30 दिनों के भीतर संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकती है, लेकिन उसे अपने साथ अपने अस्तित्व के सभी प्रमाण, वार्षिक ऑडिट अकाउन्ट्स, अंशदान एवं व्यय रिपोर्ट और पदाधिकारियों की अपडेट लिस्ट लानी होगी।

चुनावी पैनल के सूत्रों ने कहा था कि ऐसी पार्टियों के विक्षेप विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं जिन्होंने फण्ड्स और डोनेशन्स का खुलासा करने में नियम कानूनों का उल्लंघन किया है।

चुनाव आयोग ने गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल ऐसी तीन पार्टियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी व आपराधिक कार्रवाही करने के लिए बाद में राजस्व विभाग को एक रेफरेंस भेजा। राजस्व विभाग केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने बेहतर सुरक्षा कवर देकर जोखिम कम किया है, जिसका लाभ करोड़ों किसानों को मिला है। इस योजना ने दावा भुगतान में पारदर्शिता को बढ़ावा देकर किसानों में एक नया विश्वास जगाया है।"

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

सुरक्षा की सौगात

फसल बीमा पॉलिसी

अब आपके हाथ

योजना एक, लाभ अनेक

- भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में
- पंजीकरण के लिए 12 भाषाओं में एनसीआई पोर्टल एवं क्रॉप इन्शुरन्स ऐप
- पैदावार के बेहतर अनुमान के लिए आधुनिक तकनीक
- किसानों की सुविधा के लिए घर-घर पॉलिसी वितरण

योजना के 7 साल - बन रही एक नई मिसाल

- हर साल 5.5 करोड़ से अधिक किसान योजना से जुड़ रहे हैं

कृषि रक्षक

मेरी पॉलिसी मेरे हाथ

देशभर में किसानों को अब तक 1.22 लाख करोड़ रु. बीमा दावों के रूप में दिए गए, आप भी अपनी रबी फसलों का बीमा ज़रूर कराएं

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - किसान कॉल सेंटर 1800 -180-1551

pmfby PMFasalBimaYojana pmfasalbimayojana

क्यूआर कोड स्कैन करें

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908